साप्ताहिक

डाक पंजीयनः म.प्र./भोपाल/4-479/2019-21

RNI-MPHIN/2015/72544

जागत गांव हमार

पंचायत की विकास गाथा, सरकार तक

चौपाल से भोपाल तक

भोपाल, सोमवार, 19 जुलाई 2021, वर्ष-7, अंक-16

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, मुरैना से एक साथ प्रकाशित

पृष्ठ :-8, मूल्य :- 8 रुपए

अफीम उत्पादक 39 हजार किसानों का अब छिनेगा पट्टा!

आफत की फसल बनी अफीम

» मप्र में काले सोने की न अच्छी पैदावार और न क्वालिटी
» सता रहा डरः पिछले साल की तुलना में उत्पादन भी कम
» मौसम की मारः अफीम की गुणवत्ता पर भी हुआ असर
» नीमच, मंदसौर-रतलाम में तीन खंडों में जारी हुए थे पट्टे
» किसानों की मांगः सरकार फसल नुकसानी का मुआवजा दे। साथ ही नियमों में भी रियासत दी जाए, ताकि नुकसान को कम किया जा सके।

कुछ खास

» जिले के तीन खंडों में 61 हजार किलो अफीम की पैदावार
» नारकोटिक्स विभाग ने इसे करीब सात करोड़ रुपए में खरीदा
» बीते साल की अपेक्षा उत्पादन में 20 फीसदी कमी दर्ज हुई
» इस साल तीन खंड में 17170 किसानों को पट्टे जारी हुए थे
» तीन खंड़ों में 3410 किसानों ने फसल को उखड़वा लिया था
» 13400 किसानों से 61 हजार किलो अफीम की खरीदी हुई
» पिछले साल 17380 पट्टे और इस साल 17210 जारी हुए थे

संवाददाता, भोपाल

काला सोना के नाम से विख्यात अफीम की इस बार प्रदेश में पैदावर कम रही है। साथ ही क्वालिटी पर भी असर पड़ा है। ऐसा मौसम की मार के कारण होना बताया जा रहा है। अब अफीम उत्पादक किसानों को पट्टे छिनने का डर सता रहा है। नारकोटिक्स विभाग के अनुसार इस बार बीते साल की अपेक्षा उत्पादन में 20 फीसदी कमी दर्ज हुई है। इसका असर उन दवाओं पर पड़ेगा, जिनमें अफीम का उपयोग होता है। गौरतलब है कि अफीम नीति जारी होने के बाद प्रदेश के अफीम उत्पादक जिलों नीमच, मंदसौर और रतलाम में इस साल प्रथम, द्वितीय और तृतीय खंड में करीब 39 हजार किसानों को अफीम की खेती के लिए पट्टे जारी हुए थे। पानी की कमी और मौसम की बेरुखी के कारण पूरा सीजन फसल के लिए आफत भरा रहा। इसके कारण फसल बीमारियों से घिरी रही। नतीजतन औसत उत्पादन भी नहीं हुआ।

हजारों ने उखड़वा ली थी फसल

खराब फसल को देखते हुए तीनों खंड़ों में हजारों किसानों ने अफीम की फसल को उखड़वा लिया था, ताकि भविष्य में उन्हें कम उत्पादन की वजह से पट्टे से महरूम न रहना पड़े। इधर, अफीम के कम उत्पादन के चलते आगामी समय में किसानों से पट्टे छिनने का खतरा खड़ा हो गया है।

पौधों में चीरा नहीं लगाया

20 प्रतिशत किसानों ने इस साल अफीम के पौधों में चीरा नहीं लगाया और खेत को हांक दिया। ऐसे में अफीम नीति के तहत उनका अगले साल का पट्टा सुरक्षित रहेगा। 80 फीसदी किसानों ने उपज नारकोटिक्स विभाग को दी है, पर कम उत्पादन के चलते पट्टा निरस्त होने की आशंका बनी हुई है। उपज के साथ ही पट्टों पर भी संकट है।

कोरोना ने लेट की अफीम नीति

मप्र में अफीम आ उत्पादन ब्रिटिश शासन काल से हो रहा है। अफीम उत्पादन में मंदसौर जिला गढ़ रहा है, लेकिन इस बार कम उत्पादन से यह गढ़ ढहता नजर आ रहा है। कोरोना के चलते अफीम नीति 20 से 25 दिन देरी से आई, जिससे बोवनी भी लेट हुई। शीतलहर से लेकर ओलावृष्टि के रूप में प्राकृतिक मार अफीम उत्पादक किसानों पर भारी पड़ी। अब किसान सरकार से रियायत मिलने की आस बांधे बैठे हैं।

» तीनों खंडों में 17 हजार 210 किसान
» अफीम बेची-13 हजार 800 किसान
» अफीम उखड़वाई-3410 किसानों ने

प्रथम खंड

- गांव-225 और पट्टेधारी किसान-5990
- अफीम तुलाने वाले कुल किसान-4702
- कुल अफीम खरीदी-20 हजार 26 किलो
- राशि दो करोड़ 93 लाख 60 हजार रुपए

द्वितीय खंड

- गांव-215 व पट्टेधारी किसान-6216
- अफीम तुलाने वाले किसान-4854
- कुल अफीम खरीदी-21 हजार किलो
- कुल राशि दो करोड़ 62 लाख रुपए

तृतीय खंड

- गांव-237 और पट्टेधारी किसान-5004
- अफीम तुलाने वाले कुल किसान-4244
- कुल अफीम-19 हजार 36 किलो
- राशि दो करोड़ 49 लाख 64 हजार

स्त्रोतः उक्त जानकारी तीनों खंड के कार्यालयों के अनुसार है।

इनका कहना है

द्वितीय खंड में कुल 4854 किसानों से लगभग 21 हजार किलो अफीम खरीदी हुई है। इस वर्ष भी खरीदी के दौरान कोरोना महामारी का खतरा भी बना रहा। अफीम तौल के बाद सभी प्रकियाएं पूरी हो गई हैं। द्वितीय खंड में करीब 1300 से अधिक किसानों ने अफीम उखड़वाई है।

प्रियरंजन, जिला अफीम अधिकारी, द्वितीय खंड

मूंग दाल का बढ़ेगा कोटा! सीएम की तोमर से मांग

भोपाल। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से भी मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मूंग दाल की खरीद पर बातचीत की है। राज्य की एक लाख 34 हजार मीट्रिक टन दाल खरीद की इजाजत केंद्र सरकार ने दे रखी है। एमपी में इस साल मूंग दाल का 7 लाख मीट्रिक टन उत्पादन हुआ है। केंद्र सरकार से मूंग दाल की खरीद 5 लाख मीट्रिक टन करने की मांग उन्होंने की है।

सोलर लाइट से रोशन होंगे विद्युत विहीन गांव

» पायलेट प्रोजेक्टः हर जिले के दो गांवों में लगेगा सोलर संयंत्र
» पंचायत विभाग ने सभी जिला पंचायतों से मांगी जानकारी
» चयनित गांव जिला मुख्य मार्ग के नजदीक होना अनिवार्य

संवाददाता, भोपाल

मध्यप्रदेश के जिन गांवों में अभी तक बिजली नहीं पहुंची है, उन्हें सोलर लाइट से रोशन किया जाएगा। पायलेट प्रोजेक्ट के तहत प्रदेश के प्रत्येक जिले के दो-दो गांवों का चयन किया जाएगा। इनमें सोलर प्लांट व लाइट लगाने का काम टाटा पॉवर कंपनी करेगी। कंपनी पंचायतों के साथ मिलकर इन सोलर लाइटों, संयंत्रों का रख-रखाव करेगी। गांवों में सोलर लाइट और संयंत्र लगाने के संबंध में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने सभी जिला पंचायतों से जानकारी मांगी है। जनपद पंचायतों को सोलर अपन अरमाओ लगाने गांवों का डीपीआर बनाकर जिला पंचायतों को एक माह में देना होगा। यह भी बताना होगा कि इन पंचायतों में बिजली पहुंची है या नहीं।

बिजली की समस्या है, तो क्या कारण हैं। सोलर लाइट, संयंत्र लगने से गांव के लोगों को क्या लाभ होगा। जिन गांवों में सोलर लाइट लगाया जाना है, आबादी 300 से 600 सी निर्धारित की गई है। गांवों के चयन में शर्त रखी गई है कि ये गांव जिला मुख्य मार्ग के नजदीक होना चाहिए।

पंचायतों को बनाएंगे आत्मनिर्भर

सरकार पंचायतों को स्ट्रीट लाइट के जरिए बिजली की खपत कम करने के साथ ही मामले में आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रही है। जिन ग्राम पंचयातों में हैलोजन अथवा ज्यादा पावर खींचने वाले बल्ब लगे हैं, वहां बिजली-की खपत कम करने एलईडी लगाने, पानी सप्लाई के लिए नल जल योजनाओं को जोड़ने को कहा है। इसके लिए केंद्र व राज्य सरकार पंचायतों को अनुदान दे रही हैं। पंचायत, आंगनबाड़ी भवनों में भी सोलर लाइट लगाने के संबंध में जोर दे रहे हैं।

प्रभारी मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया बोले

हर ग्राम पंचायत में होंगे खेल मैदान

हेमराज मौर्य, शिवपुरी

जिले में 500 से अधिक सहरिया ग्राम चिन्हित हैं। प्रत्येक सहरिया आदिवासी परिवार का बीपीएल और आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे। इसके लिए योजना बनाकर काम शुरू करें। हर ग्राम पंचायत में खेल मैदान तैयार किए जाएंगे। इसके लिए कार्ययोजना बनाकर काम करें। स्वच्छता परिसर में पानी की व्यवस्था नहीं है वहां व्यवस्था करें। समय सीमा के साथ ही कार्य की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए। कार्य में अनियमितता करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह बात पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग एवं शिवपुरी जिले के प्रभारी मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने जिला योजना समिति की बैठक के दौरान कही। मंत्री का प्रभारी मंत्री बनाए जाने के बाद यह शिवपुरी जिले का पहला भ्रमण था। उन्होंने शिवपुरी भ्रमण के दौरान जिला योजना समिति की बैठक में विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा की और अधिकारियों को समय सीमा के साथ गुणवत्ता युक्त कार्य करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित बैठक में प्रभारी मंत्री ने ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित मनरेगा कार्यक्रम की प्रगति की जानकारी ली। गौशाला संचालन, स्वच्छता परिसर, प्रधानमंत्री आवास, स्वच्छ भारत मिशन आदि की समीक्षा की। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा संचालित नल जल योजना और मड़ीखेड़ा प्रोजेक्ट, सीवर प्रोजेक्ट की भी समीक्षा की।

- शिवपुरी में गौशाला संचालन, स्वच्छ भारत मिशन की जानी गति
- गुना के बमोरी में धनिया की प्रोसेसिंग इकाई स्थापित की जाएगी

हर गरीब को मिले राशन

प्रभारी मंत्री ने निर्देश दिए हैं कि उचित मूल्य दुकान पर कौन सेल्समैन कितने वर्षों से है। इसकी जानकारी उपलब्ध कराएं। गरीब परिवारों को नियमानुसार राशन का वितरण किया जाए। राशन वितरण व्यवस्था में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लापरवाही करने वाले दुकानदार और फूड इंस्पेक्टर दोनों के विरुद्ध कार्रवाई होगी। जिसके खिलाफ शिकायत प्राप्त होती है उस दुकानदार को तत्काल हटाए और स्व सहायता समूह को संचालन की जिम्मेदारी सौपें।

जमीन पर नहीं बैठेंगे बच्चो

प्रभारी मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि जिन स्कूलों में बाउंड्रीवॉल नहीं है उनमें पक्की बाउंड्रीवॉल बनवाई जाए। इसके अलावा बच्चे अब जमीन पर बैठकर मध्याह्न भोजन नहीं करेंगे। हर स्कूल में टेबल कुर्सी की व्यवस्था होना चाहिए।

राशन वितरण करेंगी महिलाएं

इधर, गुना जिले के बमोरी में आयोजित महिला स्व-सहायता समूह के उन्मुखी कार्यक्रम शिरकत करने पहुंचे पंचायत मंत्री सिसोदिया ने कहा कि आज मध्य प्रदेश स्वयं सहायता समूह के मामले में भारत में सबसे आगे हैं। वर्तमान में यहां 36 लाख समूह कार्यरत हैं। हमारा लक्ष्य एक लाख समूह गठित कर लोगों को आत्मनिर्भर बनाना है। अब हमारी आगे की रणनीति यह है कि स्व-सहायता समूह के उत्पादों की ब्रांडिंग कर इन्हें अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेचा जाएगा। जिससे समूहों को और अधिक लाभ होगा। गुना जिले में महिला समूह अच्छा काम कर रहे हैं। हाल ही में 75 समूहों को गेहूं खरीदी का काम दिया गया था। जिसे समूहों ने सफलतापूर्वक पूरा किया। समूह को राशन वितरण तथा इसी प्रकार के अन्य कार्य दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि बमोरी में महिला स्व सहायता समूहों के माध्यम से धनिया की प्रोसेसिंग इकाई स्थापित की जाएगी। आगामी समय में सभी उत्पाद साथी बाजार के माध्यम से बेचे जाएंगे।

-आयुक्त भू अभिलेख ने अपडेट किए रिकॉर्ड

रजिस्ट्री से पहले अब खुद जांच सकेंगे खसरा

संवाददाता, भोपाल

जमीनों की खरीद फरोख्त के दौरान हो रहे फर्जीवाड़े से बचने के लिए पंजीयन विभाग ने अपनी साइट में खसरे के कॉलम में जिले का रिकॉर्ड अपडेट किया है। आयुक्त भू अभिलेख मप्र से लिंक करने के बाद इसमें तीनों तहसीलों हुजूर, बैरसिया और कोलार के जमीन संबंधी खसरों की जानकारी उपलब्ध है। रजिस्ट्री कराने से पहले आप खुद ही खसरा नंबर से जांच कर सकते हैं। इससे आप को स्पष्ट हो जाएगा कि जमीन वाकई उसी व्यक्ति ही है जिससे आप खरीद रहे हैं या फिर किसी और की। कोरोना काल में भू-अभिलेख और पंजीयन विभाग ने जिले के एक-एक राजस्व निरीक्षण मंडल, गांव, पटवारी हल्का, भोपाल शहर के खसरों को साइट पर अपडेट कर दिया है। इसमें चाहें तो भू स्वामी के नाम से भी जमीन सर्च की जा सकती है। इससे पहले काफी लोग जमीनों की रजिस्ट्री कराने से पहले रिकॉर्ड रूम से खसरों की जानकारी निकलवाते थे। लेकिन अब ये लिंक सीधे पंजीयन विभाग की वेबसाइट एमपीआईजीआर पर उपलब्ध है। इससे रिकॉर्ड रूम में कागज निकलवाने में लगने वाले समय की बचत भी होगी।

ये फायदा होगा

जिले में कोई भी प्लॉट खरीदने से पहले उसके खसरे नंबर के आधार पर उसकी जांच कर सकते हैं। जमीन का उपयोग भी पता कर सकते हैं। ऐसे में कृषि जमीन पर कॉलोनी काटने वालों के चंगुल से बच सकते हैं। बाद में ऐसी कॉलोनियों पर प्रशासन कार्रवाई करता है। प्लॉट किस के नाम पर है, रजिस्ट्री करने वाला व्यक्ति सही है या नहीं, इसकी जानकारी भी इसमें की जा सकती है। इसे भू अभिलेख की साइट से भी लिंक किया है। इसमें किसी भी स्थान का नक्शा निकालकर उसे भी जांच सकते हैं। इसमें नक्शे पर ही खसरों के नंबर डले हैं। भूमि का प्रकार (1) शासकीय भूमि (2) निजी भूमि (3) अनलिंक भूमि, सब के बारे में बताया है।

प्रोजेक्ट की जांच भी कर सकते हैं

इसी साइट में रेरा रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन में जाकर राजधानी ही नहीं प्रदेश के किसी भी अरूव्ड बिल्डर के प्रोजेक्ट की जानकारी की जा सकती है। बिल्डर के पास किस विभाग की अनुमति है, उसका रेरा में रजिस्ट्रेशन है या नहीं। टीएंडसीपी से क्या नक्शा पास है और बिल्डर बना क्या रहा है। सब कुछ इसमें देखा जा सकता है।

गांव की स्वच्छता पर फिल्म बनाओ, दो लाख तक के पुरस्कार पाओ

» आम जनता सहित सरकारी नौकरी वाले भी बना सकते हैं फिल्म

» प्रविष्टि भेजने की अंतिम तिथि 15 अगस्त

संवाददाता, भोपाल

ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता को लेकर संदेश देती लघु फिल्म बनाकर दो लाख तक के पुरस्कार जीते जा सकते हैं। इसमें आम जनता के साथ ही शासकीय विभागों के अधिकारी-कर्मचारी भी शामिल हो सकते हैं। प्रविष्टि भेजने की अंतिम तिथि 15 अगस्त निर्धारित की गई है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की राज्य कार्यक्रम अधिकारी निधि निवेदिता द्वारा इस संबंध में पूरे प्रदेश के जिला पंचायत सीईओ को पत्र लिखा गया है। पत्र में हवाला दिया गया है कि स्वच्छ भारत मिशन के अनुसार समस्त ग्रामों को ओडीएफ प्लस की श्रेणी में लाया जाना है। गांव में किसी भी तरह की गंदगी नहीं हो, दिखने में पूर्ण रूप से स्वच्छ हो, जनता द्वारा कचरे का प्रबंधन किया जाता हो, साथ ही तरल एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व ग्राम की दृश्य स्वच्छता सुचारु रूप से चल रही हो।

1 से 5 मिनट की लघु फिल्म

लघु फिल्म प्रतियोगिता को स्वच्छ फिल्मों का अमृत महोत्सव नाम दिया गया है, जिसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोडने के लिए जिला पंचायत की टीम सक्रिय हो गई है। प्रतियोगिता में मेरा गांव-मेरा योगदान विषय पर ही 1 से 5 मिनट की लघु फिल्म बनाई जा सकती है। इसमें दो महत्वपूर्ण विषय हैं, जिसमें पहला ओडीएफ प्लस के निम्न चार घटक बायोडिग्रेडेबल कचरा, गोवर्धन, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, ग्रे वाटर मैनेजमेंट, मल कीचड़ प्रबंधन तथा व्यवहार परिवर्तन तथा दूसरा ग्रामीण क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति के आधार पर ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन पर किए गए तकनीकी विकल्प एवं स्वच्छता संदेशों पर आधारित होगी। इसमें प्रमुख रूप से समतल क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र व नदी के किनारे बसाहट है। प्रतियोगिता का प्रथम पुरस्कार 2 लाख, दूसरा 1 लाख 20 हजार तथा तृतीय पुरस्कार 80 हजार रुपए है। फिल्म हिंदी या स्थानीय भाषा का उपयोग कर बनाई जा सकती है।

यूट्यूब पर अपलोड करनी पड़ेगी फिल्म: फिल्म तैयार होने के बाद प्रतिभागी द्वारा अपनी मेल आईडी बनानी पड़ेगी और उसी के जरिए फिल्म को यूट्यूब पर अपलोड करना पड़ेगा।

कर्नाटक की कंपनी ने मध्यप्रदेश के किसानों को दिया धोखा

संवाददाता, भोपाल

पहले तो कर्नाटक की एक कंपनी ने इंदौर के देपालपुर क्षेत्र के किसानों को ज्यादा उत्पादन पैदा करने वाले बीज देकर फसल खरीदने का एग्रीमेंट किया, लेकिन जब फसल कम हुई तो खरीदने से हाथ खड़े कर दिए। अब किसान बाहरी लोगों को कम दामों पर प्याज बेचने को मजबूर हैं, जबकि कंपनी द्वारा बाकायदा किसानों से एग्रीमेंट किया गया था कि प्याज तैयार होने के बाद कंपनी खुद खरीदकर अपने वाहन से कर्नाटक ले जाएगी, लेकिन बाद में कंपनी ने हाथ ऊंचे कर दिए। देपालपुर तहसील के तलावली गांव के किसान मनमोहन पटेल सहित कुछ अन्य किसानों ने कुछ माह पूर्व साउथ की नोरा एग्रो टच कंपनी से कांटेक्ट किया। कंपनी ने किसानों को खुद प्याज के बीज दिए और कहा कि इन बीजों से प्याज की पैदावार बढ़ेगी और एक बीज से 5 से ज्यादा प्याज पैदा होंगे। गांव के 6 किसानों मोनू पटेल, संजय परमार, विनोद परमार, राम बीसी, राहुल परमार और राजेश खेर ने मिलकर 20 बीघा से अधिक खेत में प्याज की खेती की।

ले जाना था कर्नाटक: कंपनी ने एग्रीमेंट कराया था कि प्याज तैयार होने पर कंपनी द्वारा किसानों को प्याज की कीमत का भुगतान कर अपने वाहन से कर्नाटक ले जाया जाएगा। किसानों ने प्याज की खेती तो कर ली, लेकिन कंपनी द्वारा दिए गए बीजों से जब उत्पादन कम हुआ तो कंपनी ने हाथ खड़े कर दिए और कहा कि पैदावार अच्छी नहीं हुई है, इसलिए प्याज नहीं ले जा सकते। कंपनी के अधिकारियों द्वारा इंदौर के स्थानीय विक्रेताओं को फसल बेचने के लिए दबाव डाला गया और 4 किसानों को स्थानीय मंडी में कम दामों पर प्याज बेचना पड़े, जबकि 2 किसान अभी भी प्याज रखे हुए हैं।

» खेतों में प्याज उगवाए और खरीदने से कर दिया इनकार

» कंपनी ने एक बीज में छह प्याज उगने का किया था दावा

दो राज्यों में कराई थी खेती: किसानों को उम्मीद है कि भाव जल्द ही बढ़ेंगे, उसके बाद बेचेंगे। उल्लेखनीय है कि कंपनी द्वारा दिए गए बीज से जिस प्याज की उपज हुई है उसका उत्पादन केवल साउथ में ही होता है। इस प्याज की डिमांड साउथ इंडिया में ज्यादा होती है। वहां रेस्टोरेंट में सलाद में तो सर्व किया ही जाता है, आम जनता भी इसी प्याज को बड़े चाव से खाती है। साउथ में प्याज की कमी होने के चलते कंपनी ने मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र में कॉन्टेक्ट पर किसानों से इसकी खेती करवाई थी।

आय बढ़ाने का दावा भी फेल : कंपनी द्वारा यह भी बताया गया था कि इस प्याज की विशेषता यह है कि इसकी फसल मात्र 120 दिनों में ही तैयार हो जाती है, जबकि दूसरे प्याज की फसल को तैयार होने में 140 से 150 दिन लगते हैं। इसके अलावा प्याज के बीज की खरीदी का खर्च भी प्रति एकड़ 20 हजार रुपए ही आता है और जब प्याज तैयार हो जाएगा तो ज्यादा कीमत में बिकेगा, जिससे किसानों की आय में भी बढ़ोतरी होगी। कंपनी ने समझाया कि किसानों को फसल की भी चिंता नहीं करना पड़ेगी, क्योंकि कंपनी पहले से ही उनसे एग्रीमेंट कर रही है।

चंद्रकली ने डिंडोरी के 23 गांवों में लगाया चार-चांद

-माइक्रो एंटरप्राइज के जरिए लोगों को बना रहीं आत्मनिर्भर

-ग्रामीणों को सिखा रहीं बिजनेस और बचत करने का हुनार

संवाददाता, भोपाल/डिंडोरी

मध्यप्रदेश का सीमावर्ती जिला डिंडोरी छत्तीसगढ़ राज्य से लगा हुआ है। घने जंगलों वाले इस क्षेत्र में आज भी मोबाइल नेटवर्क तक ढंग से नहीं मिलता, ऊपर से नक्सलियों का खतरा भी रहता है। इस सबके बावजूद 38 साल की चंद्रकली मरकाम घने जंगलों के बीच बसे गांव-गांव में जाकर महिलाओं से मिलती हैं। उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के साथ परेशानियों को हल करने की कोशिश करती हैं। चंद्रकली खुद पांचवीं तक पढ़ी हैं, लेकिन अपने उद्यमिता कौशल और गांवों को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें 2020 में कंफेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआईआई) फाउंडेशन ने माइक्रो एंटरप्राइज श्रेणी के वुमन एक्जेम्प्लर अवॉर्ड से सम्मानित किया था।

मिलती थी 20 रुपए मजदूरी: भारिया जनजाति की चंद्रकली की जिंदगी भी आम आदिवासी महिला की तरह ही रही। 11 साल की उम्र में शादी हो गई। 20 रुपए दिन मजदूरी भी बमुश्किल मिल पाती थी। ऐसे में घर चलाना भी मुश्किल हो रहा था। चंद्रकली जब 19 साल की थीं, तो पहली बार घरवालों से छुपकर एक सामाजिक संस्था 'प्रदान' के स्व-सहायता समूह से जुड़ गईं। यह बदलाव का पहला अनुभव था। धीरे-धीरे उन्होंने सप्ताह में एक-एक रुपए बचाना शुरू किया। महिलाओं को जोड़कर बचत करने की प्रेरणा दी।

आज भी एक कमरे का मकान: डिंडोरी के इस आदिवासी बाहुल्य इलाके में आय के बहुत ज्यादा साधन नहीं हैं। 2006 में चंद्रकली ने सरकारी सहायता से पोल्ट्री फार्मिंग की तरफ कदम रखा और भूमिहीन परिवारों के लिए पोल्ट्री फार्म को-ऑपरेटिव बनाई। शुरुआत में इससे 60 लोग जुड़े। अब इस समूह में 23 गांवों की महिलाएं जुड़ी हैं। चंद्रकली कहती हैं कि हालांकि तस्वीर बहुत नहीं बदली है, आज भी वह एक कमरे के मकान में रहती हैं, उनकी खुद की बचत 18 हजार 900 रुपए है। लेकिन एक उम्मीद से कहती हैं कि बदलाव की शुरुआत हो गई है।

5वीं पास, करोड़ों का कारोबार : चंद्रकली सिर्फ सिग्नेचर करना जानती हैं, लेकिन महिला साथियों के साथ मिलकर पोल्ट्री का कारोबार संभाल रही हैं। उनके नेतृत्व में 23 गावों की 476 महिला किसान पोल्ट्री फार्मिंग करती हैं। पोल्ट्री फार्म का 2018-19 में 14. 5 करोड़ और 2019-20 में 18 करोड़ रुपए टर्नओवर रहा। बचत भी 8 लाख के आसपास रही। इसके लिए अकाउंटेंट और मैनेजर रखे हुए हैं। सारा कामकाज हिंदी में होता है। उन्होंने 507 स्व-सहायता समूहों को जोड़कर उनका महासंघ बनाया है।

'हलचलित महिला किसान' सोसायटी बनाई: चंद्रकली अब महिला किसानों को पहचान और सही दाम दिलाने की दिशा में काम कर रही हैं। वह कहती हैं कि खेत पर महिलाएं पुरुषों से ज्यादा काम करती हैं, लेकिन उन्हें श्रेय नहीं मिल पाता। इसके लिए उन्होंने 'हलचलित महिला किसान' नाम से कोऑपरेटिव सोसायटी बनाई है। चंद्रकली आदिवासी अंचलों में महिलाओं की पढ़ाई की भी वकालत करती हैं। वह उच्च शिक्षा की सुविधाएं जैसे मुद्दे भी उठाती रहती हैं। वह आय के दूसरे साधन विकसित करने के लिए मशरूम की खेती के साथ किचन गार्डन विकसित करने के लिए प्रेरित कर रही हैं।

अब पटवारी भी आंदोलन की राह पर

- सिर्फ भू-अभिलेख से जुड़े नक्शा, खसरा और बी-1 के ही काम करेंगे, अगस्त में तीन दिन का सामूहिक अवकाश
- प्रदेश पटवारी संघ ने भोपाल में हाल ही में मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को ज्ञापन सौंपा
- मध्यप्रदेश में कर्मचारियों के प्रदर्शन पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का सरकार पर तंज

संवाददाता, भोपाल

मध्यप्रदेश में अब पटवारी भी आंदोलन की राह पर हैं। अपनी तीन सूत्रीय मांगों के समर्थन में मध्य प्रदेश के सभी पटवारियों ने भू-अभिलेख को छोड़कर अन्य किसी प्रकार के काम नहीं करने का फैसला किया है। वे सिर्फ भू-अभिलेख से जुड़े नक्शा, खसरा और बी-1 के काम ही करेंगे। इधर, मध्य प्रदेश में कर्मचारियों के प्रदर्शन पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने प्रदेश सरकार पर तंज किया है। शिवराज सरकार की तानाशाही से मप्र में हड़तालें हो रही हैं। गौरतलब है कि प्रदेश में 19 हजार से अधिक पटवारी हैं, जो 25 जून से चरणबद्ध तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। अब तक तहसील व जिला स्तर पर कलेक्टर व तहसीलदारों को ज्ञापन सौंपे जा चुके हैं। वहीं काली पट्टी बांधकर काम भी किया। अब भू-अभिलेख को छोड़ शेष सभी कार्यों को बहिष्कार कर दिया है। मध्य प्रदेश पटवारी संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि इस समय पटवारी अपने कार्यों के साथ सरकार के अन्य 56 विभागों के विभिन्न कार्य कर रहे हैं। बावजूद उनकी मांगों को लेकर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। इसलिए अब आंदोलन कर रहे हैं।

ये हैं मांगें

» पटवारियों का ग्रेड पे 2800 करते हुए समय मान वेतनमान विसंगति को दूर किया जाए।

» गृह जिले में तैनाती हो। वर्तमान में कई पटवारियों को गृह जिले से दूर पदस्थ किया है।

» नवीन पटवारियों की सीपीसीटी की अनिवार्यता संबंधी नियम तत्काल समाप्त किया जाए।

प्रदर्शन

» 12 जुलाई को भू-अभिलेख को छोड़ सभी कार्यों का बहिष्कार किया।

» 2 से 4 अगस्त तक सामूहिक रूप से तीन दिन की हड़ताल पर रहेंगे।

» तीन अगस्त को जिला स्तर पर रैली निकालकर ज्ञापन सौंपे जाएंगे।

» 5 अगस्त को वेब पोर्टल जीआईएस व ऑनलाइन कार्यों का बहिष्कार।

» 10 अगस्त को पटवारी अनिश्चितकालीन कलमबंद हड़ताल पर चले जाएंगे।

औषधि वन से वनवासियों की बदलेगी किस्मत

» कदवाल वीट में सौ हेक्टेयर में तैयार होगा वन » कराहल रेंज में रोपे जाएंगे कई औषधी पौधे

संवाददाता, श्योपुर

वन विभाग करीब 100 हेक्टेयर में औषधि वन तैयार कर रहा है। जिसमें विभिन्न प्रकार की जड़ी-बूटी और औषधि युक्त पौधे लगाए जाएंगे। यह औषधि वन, वन क्षेत्र में रहने वाले लोगों की किस्मत बदलेगा, क्योंकि इस वन से वनवासी लोग जड़ी-बूटी एकत्रित करके उसे शासन से अधिकृत जड़ी-बूटी खरीदारों के यहां बेच सकेंगे, इससे उन्हें आमदनी होगी और उनकी आर्थिक स्थिति भी सुधेरी।

सामान्य वन मंडल कराहल के प्रभारी रेंज ऑफिसर बीएल अनंत के मुताबिक कदवाल उत्तर वीट की 100 हेक्टेयर वन भूमि पर औषधि वन तैयार किए जाने का काम वर्ष 2018-19 से किया जा रहा है। दस साल में जाकर यह औषधि वन खड़ा हो जाएगा। यहां हर साल 10-10 हेक्टेयर में पौधों का रोपण किया जाएगा। इस तरह दस साल में इस पूरे क्षेत्र में औषधि युक्त पौधों का रोपण हो जाएगा।

इन औषधि पौधों का होगा रोपण

कदवाल उत्तर वीट में विकसित किए जाने वाले होने वाले औषधि वन में वन विभाग के द्वारा वील, आंवला, बहेड़ा, कुल्लू, सतावर, बुरेटा, पलास, महुआ, आदि औषधि पौधों का रोपण करेगा। डीएफओ सुधांशु यादव बताते हैं कि ये काफी दुर्लभ औषधि पौधे हैं, जिनका उपयोग कई तरह की आयुर्वेदिक दवाइयां बनाने में होता है।

100 हेक्टेयर में कदवाल वीट में तैयार होगा औषधि वन

10 साल का समय लगेगा औषधि वन को तैयार होने में

250 हेक्टेयर में खोरी वीट में तैयार हो गया औषधि वन

हर साल 4-5 हजार लोग कमा रहे मुनाफा

वन विभाग ने कराहल रेंज की खोरी वीट में औषधि वन तैयार कर लिया है। सामान्य वन मंडल के डीएफओ सुधांशु यादव का कहना है कि 5 साल की मेहनत के बाद इस औषधि वन को तैयार किया है। 250 हेक्टेयर के इस औषधि वन में महुआ, बेल, आंवला, अमलतास, करंज, बेहड़ा, अर्जुन, सीताफल, नीम, अश्वगंधा आदि औषधि पौधे लगाए गए हैं, जो अब न सिर्फ वृक्ष बन गए हैं, बल्कि इनसे जड़ी-बूटी का संग्रहण भी किया जाने लगा है। हर साल इस औषधि वन से करीब 4-5 हजार वनवासी लोग न सिर्फ जड़ी-बूटी का संग्रहण कर रहे हैं, बल्कि उन्हें बेचकर मुनाफा भी कमा रहे है।

इनका कहना है

खोरी के जंगल में औषधि वन विकसित हो गया है। इस औषधि वन से हर साल 4-5 हजार लोग लाभांवित हो रहे हैं। ऐसा ही औषधि वन अब कदवाल वीट में भी विकसित किया जा रहा है। इसके जरिए भी वनवासी लोगों को लाभांवित किया जाएगा।

सुधांशु यादव, डीएफओ,
सामान्य वन मंडल श्योपुर

कृषि को लाभ का व्यवसाय कैसे बनाएं

डॉ. सत्येंद्र पाल सिंह,
प्रधान वैज्ञानिक एवं
प्रमुख कृषि विज्ञान
केंद्र, मुरैना

जिस तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है उसके अनुपात में कृषि योग्य भूमि कम होती जा रही है। देश में आज अधिकांश किसान सीमांत एवं छोटे किसानों की श्रेणी में आते हैं जिनके पास एक से लेकर दो एकड़ तक ही भूमि उपलब्ध है। ऐसे में किसानों की आय बढ़ाने का कार्य अत्यधिक चुनौती पूर्ण हो जाता है। बावजूद इसके खेती को लाभ का व्यवसाय बनाने के प्रयास देश-प्रदेश की सरकारों द्वारा किए जा रहे हैं।

जिस तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है उसके अनुपात में कृषि योग्य भूमि कम होती जा रही है। देश में आज अधिकांश किसान सीमांत एवं छोटे किसानों की श्रेणी में आते हैं जिनके पास एक से लेकर दो एकड़ तक ही भूमि उपलब्ध है। ऐसे में किसानों की आय बढ़ाने का कार्य अत्यधिक चुनौती पूर्ण हो जाता है। बावजूद इसके खेती को लाभ का व्यवसाय बनाने के प्रयास देश-प्रदेश की सरकारों द्वारा किए जा रहे हैं। कृषि को लाभ का व्यवसाय कैसे बनाएं इसके लिए किसानों को खेती के साथ-साथ कृषि विविधीकरण को अपनाने की जरूरत है। खेती को लाभ का व्यवसाय बनाने के लिए सबसे पहले खेती किसानी पर आ रही कृषि लागत को कम करने की जरूरत है। खेती में काम आने वाले बीज, कृषि रसायन, उर्वरक, कृषि क्रियाएं, सिंचाई आदि पर साल दर साल लागत बढ़ती चली जा रही है। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि खेती पर आने वाली लागत को कम किया जाए जिससे किसानों के मुनाफे में वृद्धि हो सके। खेती पर आने वाली लागत को कम करने के लिए सबसे जरूरी बिंदु मिट्टी की जांच का है, क्योंकि किसानों द्वारा बिना सोचे समझे, बिना फसलों की आवश्यकता के अनावश्यक रूप में असंतुलित मात्रा में रासायनिक खादों का प्रयोग किया जा रहा है। जिससे फसलों पर आने वाली लागत बढ़ रही है। इस लागत को मिट्टी की जांच कराकर कम किया जा सकता है। जिसके आधार पर फसल को आवश्यकता के अनुरूप संतुलित मात्रा में रासायनिक खाद प्रयोग में लाई जा सके। लागत कम करने के लिए दूसरा प्रमुख बिंदु जैविक खादों को खेतों में अधिकाधिक रूप से प्रयोग में लाने की आवश्यकता है। जैविक खादों के प्रयोग से भूमि की उर्वरा शक्ति में बढ़ोत्तरी होगी, जमीन की जलधारण क्षमता में वृद्धि होगी, वायु स्पेस बढ़ेगा, फसलों के उत्पादन में वृद्धि होने के साथ ही रासायनिक खादों पर निर्भरता काफी कम हो जाएगी। अत: किसानों को चाहिए कि वह अपने घर पर ही केंचुए की खाद, गोबर की खाद, नाडेप कम्पोस्ट आदि तैयार कर हर साल खेतों में डालें। इससे किसानों को आशातीत लाभ होगा और कृषि लागत में कमी आएगी। किसानों को फसलों से अधिक उत्पादन लेने की आवश्यकता है। इसके लिए किसानों को उन्नतशील प्रजातियों के बीजों को प्रयोग में लाना होगा। उन्नतशील प्रजातियों के बीजों के प्रयोग से फसलों के उत्पादन में 20-22 प्रतिशत तक की बढ़ोत्तरी देखी गयी है। जब फसलों का उत्पादन बढ़ेगा तो निश्चित रूप से किसानों को ज्यादा मुनाफा मिल सकेगा। अत: किसानों को कृषि विश्वविद्यालयों एवं शोध संस्थानों से ईजाद की गई प्रजातियों के बीजों के अलावा उन्नतशील प्रजातियों के बीजों का ही प्रयोग करना चाहिए। कृषि आय को बढ़ाने और आने वाली लागत में कटौती करने के लिए किसानों को नवीनतम कृषि तकनीकों को अमल में लाने की जरूरत है। आज खेती में नवोन्मेंषी तकनीकों का प्रयोग बहुतायत में किया जा रहा है। खेती में प्रयोग आने वाले नए-नए कृषि यंत्र एवं नई-नई कृषि तकनीकें वैज्ञानिकों द्वारा विकसित की जा चुकी हैं। अत: किसान इनको प्रयोग में लाकर मजदूरी, समय, श्रम, धन आदि की बचत करने के साथ ही अधिक उत्पादन ले सकते हैं। किसानों को अधिक लाभ लेने के लिए नियमित तौर पर फसल चक्र प्रणाली को भी अमल में लाने की आवश्यकता है। जिससे अच्छा उत्पादन लेने के साथ ही भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहे और फसलों में खरपतवार एवं कीट पतंगों के प्रकोप को कम किया जा सके। अत: खाद्यान्न फसल के बाद दलहन, तिलहन आदि फसलों का समावेश फसल चक्र में करना चाहिए। किसान परंपरागत फसलों के अलावा अधिक मुनाफा देने वाली नगदी फसलों को भी अपने फसल चक्र में शामिल करें जिससे उनकी आय में बढ़ोत्तरी हो सके। खेती को लाभ का सौदा बनाने के लिए किसानों को फसल विविधिकरण अपनाने की आवश्यकता है। जिसमें फल-फूल की खेती, सब्जी उत्पादन, औषधि फसलें, दलहनी फसलें आदि को उगाना होगा। जिसमें परम्परागत फसलों से ज्यादा लाभ प्राप्त होता है। भारतीय कृषि पूरी तरह से मौसम पर आधारित है। कई वार मौसम के प्रकोप से किसानों की फसलें पूरी तरह से तबाह हो जाती हैं। आंधी, तूफान, वर्षा, ओले, बाढ़, अतिवृष्टि जैसे प्रकोप देखते ही देखते खड़ी फसलों को तबाह कर देते हैं। इनसे बचाव के लिए भारत सरकार द्वारा किसानों के लिए चलाई जा रही फसल बीमा योजना का लाभ किसानों को उठाना चाहिए और अपनी खरीफ, रबी, जायद और उद्यानिकी आदि फसलों का समय रहते बीमा करा लेना चाहिए। जिससे अतिवृष्टि की स्थिति में फसलों में हुई क्षति का पूर्ण भुगतान फसल बीमा के माध्यम से प्राप्त हो सके। अच्छा उत्पादन लेने के साथ ही किसानों को उनके उत्पादों का तब तक उचित लाभ नहीं मिल सकता जब तक कि किसान अपने कृषि उत्पाद को उचित दरों पर बिक्री नहीं कर लेता है। इसलिए कृषि को लाभ का व्यवसाय बनाने के लिए किसान सही समय पर उचित दरों पर अपने कृषि उत्पादों को बिक्री करें। जिससे उन्हें अधिक लाभ हो सके। चतुर किसान वही है जिसकी एक नजर खेत पर तथा दूसरी नजर बाजार पर होती है। कृषि में विविधीकरण का एक प्रमुख आयाम पशुपालन भी है। पशु पालन के माध्यम से डेयरी व्यवसाय, बकरी पालन, मुर्गी पालन आदि के अलावा मछली पालन, मधुमक्खी पालन, मशरूम उत्पादन, रेशम कीट उत्पादन आदि सहयोगी व्यवसाय अमल में लाकर अपनी आमदनी दुगुनी से ज्यादा बढ़ा सकते हैं। पशुओं से मिलने वाला गोबर आदि जैविक खाद के रूप में खेतों में काम आ सकेगा। इतना ही नहीं, अपितु फसल खराब होने की स्थिति अथवा एक धंधे में नुकसान होने की स्थिति में दूसरे कृषि आधारित धंधे से लाभ प्राप्त होने से आजीविका बेहतर तरीके से संचालित हो सकेगी। किसानों को चाहिए कृषि उत्पादों का अधिक से अधिक लाभ लेने के लिए खेती एवं पशुओं से प्राप्त होने वाले उत्पादों का मूल्यसंर्वधन करके और अधिक मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। डेयरी व्यवसाय भी लाभ का व्यवसाय बनता जा रहा है। खेती के साथ ही इस व्यवसाय को छोटे-बड़े सभी किसान आसानी से कर सकते हैं। खेती से ही अनाज, चारा, दाना डेयरी पशुओं के लिए प्राप्त होता है। डेयरी उत्पादों की मांग भी तेजी से बढ़ रही है। सीमांत एवं भूमिहीन किसान जिनके पास कम पूंजी तथा कम जमीन है। वह बकरी पालन जैसे व्यवसाय करके अतिरिक्त आमदनी प्राप्त कर सकते हैं।

सहकारिता मंत्रालय को बनाना होगा पारदर्शी

केंद्र सरकार में सहकारिता मंत्रालय का गठन देश में सहकारिता से जुड़ी करोड़ों जिंदगियों के लिए सुखद संदेश है। मालूम हो कि सहकारी संस्था अमूल की कारोबारी सफलता ने लाखों जिंदगियों को गुणवत्ता प्रदान करने का कार्य किया है। दुग्ध क्रांति के साथ ही इसने किसानों को आय का एक स्थायी स्रोत मुहैया कराया है। शहर से लेकर गांव तक सहकारी बैंकों ने उस तबके तक बैंकिंग सुविधा पहुंचाने का कार्य किया है, जो अर्थव्यवस्था में अंतिम पायदान पर खड़ा है। दूध और चीनी से लेकर दैनिक जरूरत की हर वस्तु और सेवाएं उपलब्ध कराने में सहकारी समितियां आगे बढ़ रही हैं। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की 2019-2020 की रिपोर्ट के मुताबिक सहकारी डेयरी ने 1.7 करोड़ सदस्यों से प्रतिदिन 4.80 करोड़ लीटर दूध खरीदा। चीनी उत्पादन के क्षेत्र में सहकारी मिलों की हिस्सेदारी लगभग 35 प्रतिशत है। भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ द्वारा जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक 2017 तक देश में 8 लाख 54 हजार 355 सहकारी समितियां थीं। इनमें सदस्यों की संख्या 30 करोड़ से अधिक है। कृषि क्षेत्र में सहकारी समितियां किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक और रियायती दर पर ऋण उपलब्ध कराने से लेकर कृषि उत्पादों का उचित मूल्य मुहैया कराने का कार्य करती हैं। मत्स्य पालन, चाय बागानों में कार्य करने वाले श्रमिकों से लेकर बुनकरों की जिंदगी को सहकारी समितियां संवार रही हैं। हमारी जिंदगी को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने वाले 55 क्षेत्रों में आज सहकारी समितियां कार्य कर रही हैं। ग्रामीण इलाकों में सहकारिता की बुनियाद पर स्वास्थ्य क्षेत्र की भी आधारभूत संरचना खड़ी हो रही है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम आयुष्मान सहकार योजना संचालित कर रहा है। इसके अंतर्गत ग्रामीण इलाकों में अस्पताल खोलने के लिए सस्ती दर पर कर्ज मुहैया कराया जाना है। सहकारी गतिविधियों पर आधारित उद्यम अब अंतरराज्यीय स्वरूप ग्रहण कर रहे हैं। देश में मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसायटी की संख्या भी करीब डेढ़ हजार हो चुकी है। सहकारिता के इतने व्यापक क्षेत्र के लिए लंबे समय से प्रशासनिक नियमन, और नीतिगत ढांचा उपलब्ध कराने की मांग चल रही थी। दरअसल सहकारिता मानव जीवन के उत्थान के लिए नैसर्गिक रूप से व्यवहार में लाई गई वह कार्यसंस्कृति है, जिसमें सबकी भागीदारी को वरीयता दी जाती है। इस व्यवस्था में अभावग्रस्त और शोषित वर्ग को मालिकाना हक के साथ आर्थिक प्रकल्प संचालित करने की सुविधा मिलती है। हालांकि सहकार आधारित उद्यम की ये गतिविधियां पूरी तरह साफ-सुथरी और दोषरहित हैं, ऐसा नहीं है। सहकारिता के 120 वर्ष की विकास यात्रा का अध्ययन करने से पता चलता है कि वित्त, मानव संसाधन और नीतिगत स्पष्टता का अभाव इस क्षेत्र की बड़ी चुनौती है। सहकारी संस्थाओं में निर्णय लेने की स्वतंत्रता ने इस क्षेत्र के अवसरों को धूमिल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। कार्यविधि तथा प्रोन्नति संबंधी नीतियों में यहां कई तरह की विसंगतियां हैं। प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां और स्वयं सहायता समूह अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने तथा विपणन व्यवस्था बाधित होने की समस्या से जूझ रहे हैं। जाहिर है, यह सब सरकारी निगरानी के अभाव का परिणाम है। येन केन प्रकारेण कुछ ही परिवार और समूह के सदस्य इन संस्थाओं में निर्वाचित तो कभी मनोनीत होते हैं।

शिक्षा-परीक्षा की राह में रोड़ा बनी कोरोना महामारी

आलोक मिश्रा

पिछले एक-डेढ़ साल के कोरोना काल में जीवन का शायद ही कोई अन्य पहलू इतने नाटकीय रूप से प्रभावित हुआ हो, जितना प्रभाव इस दौरान शिक्षा के क्षेत्र पर पड़ा है। कोविड महामारी ने स्कूल और कॉलेज के जीवन को एकदम बदलकर रख दिया है।

पिछले एक-डेढ़ साल के कोरोना काल में जीवन का शायद ही कोई अन्य पहलू इतने नाटकीय रूप से प्रभावित हुआ हो, जितना प्रभाव इस दौरान शिक्षा के क्षेत्र पर पड़ा है। कोविड महामारी ने स्कूल और कॉलेज के जीवन को एकदम बदलकर रख दिया है। कोरोना वायरस की भयावहता ने पारंपरिक शिक्षा एवं परीक्षाओं की राह निरंतर रूप से बाधित की हुई है। परंपरावादी इससे मायूस हैं। ऑनलाइन शिक्षा की स्थिति आदर्श तो नहीं, परंतु परिस्थितियों को देखते हुए फिलहाल सबसे उपयुक्त विकल्प लगती है। वैसे भी ऑनलाइन शिक्षण एवं मूल्यांकन की पद्धतियां अभी विकास के चरण में ही हैं। शिक्षा तंत्र के विभिन्न स्तरों पर चर्चा जारी है कि इसमें कोई कारगर प्रणाली विकसित की जाए। इस पर आए सुझाव कुछ चिंताएं भले ही दूर करते हैं, किंतु कई प्रश्न भी उठाते हैं। इससे यही प्रतीत होता है कि अहम मुद्दे अनसुलझे ही हैं। भारतीय स्कूली छात्र के लिए 12वीं की बोर्ड परीक्षा सबसे महत्वपूर्ण होती है। यही परीक्षा उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश की सबसे स्वीकार्य कसौटी भी है। कोविड के कारण जहां इस साल 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी गई। वहीं अगले सत्र के लिए उसका प्रारूप बदल दिया गया। प्रस्तावित परीक्षा दो चरणों में होगी। ऑनलाइन परीक्षा की स्थिति में मूल्यांकन में आंतरिक आकलन और पूर्व परीक्षाओं को भी जोड़ा जा रहा है, मगर स्नातक कक्षाओं में प्रवेश के लिए 12वीं के परिणाम की महत्ता कम नहीं हुई है। यह बिंदु हमें देश में स्नातक कक्षाओं में प्रवेश की वास्तविक समस्या से साक्षात्कार कराता है। कुछ कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए भारी दबाव है। उनमें जितने आवेदन आते हैं, उस अनुपात में प्रवेश देना असंभव है। इसका परिणाम निकलता है आसमान छूती कटऑफ सूची में। हर साल कुछ सबसे वांछित कॉलेजों में प्रवेश के लिए अर्हता सूची के 98 प्रतिशत या उससे भी अधिक के बेतुके स्तर पर जाने के समाचार आते हैं। मिसाल के तौर पर दिल्ली विश्वविद्यालय के किसी प्रतिष्ठित कॉलेज में अंग्रेजी ऑनर्स में प्रवेश के इच्छुक आवेदक को 12वीं कक्षा में न केवल अंग्रेजी, बल्कि गणित, भौतिकी और अपने अन्य विषयों में भी 98 प्रतिशत अंक लाने आवश्यक होंगे। इस तंत्र से मार खाए कुछ साधनसंपन्न छात्र स्नातक के लिए विदेश की उड़ान पकड़ लेते हैं। असल में प्रतिभा पलायन का अभिशाप स्कूली शिक्षा की समाप्ति के साथ ही शुरू हो जाता है। हमें उच्च शिक्षा के लिए और गुणवत्तापरक संस्थानों की आवश्यकता है, जहां औसत अंक पाने वाले मध्यम प्रतिभा वाले छात्रों के लिए भी गुंजाइश हो। वर्तमान परिदृश्य में एक छात्र को प्रवेश मिलता है तो सैकड़ों वंचित रह जाते हैं। इसमें हमारे छात्रों की आकांक्षाएं पूरी नहीं हो सकतीं।

नए कॉलेजों के साथ यह भी उतना आवश्यक है कि वे छोटे और मझोले शहरों में हों ताकि देश भर के छात्रों का जमावड़ा कुछ चुनिंदा मेट्रो शहरों में लगने की प्रवृत्ति पर लगाम लग सके। इस मोर्चे पर दूरस्थ डिजिटल शिक्षा पथ प्रदर्शक साबित हो सकती है। कनेक्टिविटी और सक्षमता जैसी वर्तमान चुनौतियों के बावजूद ऑनलाइन माध्यम में शिक्षा का कायाकल्प करने की अकूत संभावनाएं हैं। भारतीय स्कूल प्रणाली में कई शिक्षा बोर्ड हैं। प्रत्येक राज्य का अपना शिक्षा बोर्ड है। वहीं सीबीएसई जैसा एक अखिल भारतीय बोर्ड भी है। विभिन्न बोर्ड में न केवल पाठ्यक्रम, बल्कि परीक्षा एवं मूल्यांकन के पैमाने भी अलग हैं, जबकि उनके छात्र उच्च शिक्षा के लिए समान सीटों पर प्रतिस्पर्धा करते हैं। कुछ राज्य बोर्ड मूल्यांकन के लिए अपेक्षाकृत सख्त मापदंड अपनाते हैं, जहां सबसे मेधावी छात्र भी 90 प्रतिशत से अधिक अंकों के लिए संघर्ष करते हैं। इसके उलट सीबीएसई में शत प्रतिशत अंक प्राप्त करना भी हैरत में नहीं डालता। ऐसे में प्रत्येक बोर्ड में पर्सेंटाइल सिस्टम बराबरी वाली व्यवस्था बनाएगा। यह छात्रों के सापेक्ष प्रदर्शन को दर्शाता है। इस तंत्र के तहत संभव है कि सख्त मूल्यांकन वाले किसी बोर्ड के 80 प्रतिशत अंकों को भी सीबीएसई जैसे उदार बोर्ड के 90 प्रतिशत से अधिक वरीयता दी जाए। अधिकांश विकसित देशों में इसका व्यापक उपयोग किया जाता है। दुर्भाग्यवश इस अतिआवश्यक मानकीकरण या बराबरी की व्यवस्था को अभी भारत में आजमाया जाना शेष है। महामारी के कारण पारंपरिक बोर्ड परीक्षाओं के रद होने की स्थिति में सीबीएसई ने छात्रों के मूल्यांकन का नया तरीका तलाशा है।

सब्जियों से कैसे कमाएं मुनाफा, कृषि वैज्ञानिकों ने दिए टिप्स

टीकमगढ़: किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की चल रही कवायद

संवाददाता, टीकमगढ़। कृषि विज्ञान केंद्र टीकमगढ़ के उद्यानिकी वैज्ञानिक डॉ. एसके सिंह और वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. बीएस किरार द्वारा खरीफ-2021 की मुख्य सब्जियों के लिए किसानों को उचित सलाह दी जा रही है। साथ ही यह भी बताया जा रहा है कि किसान किस किस्म के बीजों की बोवनी करें और कितनी मात्रा में किस खाद का इस्तेमाल करें। ताकि किसानों को कम लागत में ज्यादा मुनाफा मिल सके।

टमाटर की उन्नत किस्में: काशी अमन, काशी विशेष, काशी अमृत व संकर किस्में- अर्का रक्षक, अर्का सम्राट, काशी अभिमान, काशी अभय आदि किस्मों के बीज की मात्रा मुक्त परागित किस्मों 350-400 ग्राम संकर किस्मों 200-250 ग्राम प्रति हेक्टेयर और उर्वरक में नत्रजन 100 किग्रा, फास्फोरस 80 किग्रा और पोटाश 60 किग्रा प्रति हेक्टेयर की दर से बोवनी से पूर्व व्यवस्था की जाए।

बैगन की उन्नतशील किस्में: पंजाब सदाबहार, पंत सम्राट, काशी तरु, काशी संदेश, पंत ऋतुराज, काशी उत्तम, काशी प्रकाश, रामनगर जायंट आदि किस्मों के बीज की मात्रा 350-400 ग्राम प्रति हेक्टेयर एवं उर्वरक की मात्रा नत्रजन 80 किग्रा, फास्फोरस 60 किग्रा, और पोटाश 50 किग्रा प्रति हेक्टेयर की दर से बोवनी से पूर्व व्यवस्था कर ली जाए।

मिर्च की उन्नतशील किस्में: जवाहर मिर्च-148, पूसा सदाबहार, पूसा ज्वाला, भाग्यलक्ष्मी, जवाहर मिर्च-283, काशी अनमोल, अर्का मेघना, अर्का हर्षिता, दिशा आदि किस्मों के बीज की मुक्त परागित किस्मों के लिए 300-350 ग्राम और संकर किस्मों के लिए 250-300 ग्राम प्रति हेक्टेयर साथ ही उर्वरक नत्रजन 120 किलो, फास्फोरस 60 किलो और पोटाश 80 किग्रा. प्रति हेक्टेयर की दर से व्यवस्था कर ली जाए।

लोबिया: काशी उन्नत, काशी कंचन, काशी निधि, पूसा कोमल, अर्का समृद्धि एवं अर्का गरिमा बीज की मात्रा 18-20 किग्रा प्रति हेक्टेयर एवं उर्वरक की मात्रा नत्रजन 30 किग्रा, पोटाश 60 किग्रा व फास्फोरस 60 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से व्यवस्था कर ली जाए।

अरबी :- इंदिरा अरबी, नरेंद्र अरबी-1, पंजाब अरबी-1, आजाद अरबी, पंचमुखी, श्री पल्लवी, श्री रश्मि, उर्वरक की मात्रा नत्रजन 80 क्लिो, फास्फोरस 60 किलो और पोटाश 80 किग्रा, प्रति हेक्टेयर व प्रकंद अथवा बीज की मात्रा 18-20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से व्यवस्था कर ली जाए।

भिंडी: काशी प्रगति, काशी विभुति, काशी क्रांति, काशी सातधारी, सारिका, हरिता, सिंजेंटा-152, यूएस-7109, महिको 8888 बीज की मात्रा 12-15 किग्रा प्रति हेक्टेयर एवं उर्वरक की मात्रा नत्रजन 100 किग्रा, फोस्फोरस 50 किलो और पोटाश 50 किग्रा प्रति हेक्टेयर की दर से व्यवस्था कर ली जाए।

30 रुपए में मिल रहा मुनगा का पौधा

इधर, कृषि विज्ञान केंद्र, टीकमगढ़ के द्वारा तमिलनाडू कृषि विवि द्वारा विकसित मुनगा संकर किस्म पीकेएम-1 (बारहमासी) का पौध उपलब्ध है, जो 8 से 10 महिनों मे फल देने लगती है। इसकी फल्लियों और पत्तियों में कार्बोहइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम, फास्फोरस व लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कुपोषण दूर करने के लिए मुनगा सर्वोत्तम माना गया है। इसको दृष्टिगत रखते हुए कृषि विज्ञान केंद्र उपरोक्त मुनगा किस्म को पौध विक्रय के लिए 30 रुपए प्रति पौध उपलब्ध है। इच्छुक किसान/व्यक्ति /संस्था डॉ. एसके सिंह, वैज्ञानिक (उद्यानिकी) से इस नंबर 7999344526 पर से संपर्क कर प्राप्त कर सकते हैं।

कृषि विज्ञान केंद्र लहार में हुआ पौधरोपण

संवाददाता, भिंड

शुक्रवार को कृषि विज्ञान केंद्र लहार में केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख, डॉ. पुनीत कुमार राठौर की अध्यक्षता में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का 93वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कृषि उपज मंडी समिति, लहार के अध्यक्ष एवं विधायक प्रतिनिधि उदय प्रताप सिंह सेंगर थे। सबसे पहले कार्यक्रम में देश के अन्य कृषि विज्ञान केंद्रों के समान केंद्र के परिसर में बाउंड्री के आसपास पूर्व से खोदे गए गढ्ढों में किसानों, महिला कृषकों और केंद्र के वैज्ञानिकों व कर्मचारियों की उपस्थिति में गुड़हल, कनेर, नीम ओर फलदार वृक्षों के 60 पौधों का रोपणकराया गया। पौधारोपण के बाद केंद्र के सभागार में उपस्थित किसानों को वैज्ञानिकों द्वारा पौधरोण के महत्व के बारे में समझाइश देते हुए जागरूक किया गया।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि द्वारा उपस्थित जनसमुदाय को वृक्षों के महत्व के बारे में संबोधित किया गया। उद्यानिकी विभाग के प्रतिनिधि कुलदीप सिंह राजपूत द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित मोबाईल एप वायुदूत के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। कार्यक्रम का संचालन कृषि प्रसार वैज्ञानिक, डॉ. रुपेंद्र कुमार द्वारा किया गया। आभार प्रदर्शन केंद्र के कृषि अर्थशास्त्र वैज्ञानिक, डॉ. अवधेश सिंह द्वारा किया गया।

बारिश के सीजन पशुओं का रखें ध्यान

पशुओं को बरसाती संक्रमण से बचाने कराएं टीकाकरण

संवाददाता, रतलाम

जावरा कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉ. सर्वेश त्रिपाठी ने पशुपालकों को सलाह दी की हर हाल में पशुपालन को व्यवसायिक रूप से बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक तकनीक को अपनाना फायदेमंद होगा। उन्होंने कहा कि बारिश के सीजन में पशुओं की देख-रेख पर विशेष ध्यान देना चाहिए। पशुपालन हर दृष्टिकोण से लाभ का व्यवसाय है। ऐसे में पशुओं के आहार एवं स्वास्थ्य प्रबंधन पर विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। आहार प्रबंधन के लिए हरे चारे के साथ-साथ सूखा चारा और उचित मात्रा में राशन देने से पशुओं की उत्पादकता पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। हरे चारे की उपलब्धता से दुधारू पशुओं की भोज्य व्यवस्था को सुदृढ़ व पशुओं के पोषण पर होने वाले खर्च को भी कम किया जा सकता है। इसलिए इस समय पशुपालक और किसान हरे चारे की फसलें मक्का, बाजरा, एमपी चरी, ज्वार नेपियर, घास इत्यादि की बोवनी करते हैं तो आने वाले समय के लिए चारे की उपलब्धता बनी रहेगी। डॉ. सुशील कुमार ने पशुपालकों से आह्वान किया है कि पशुओं में विभिन्न प्रकार के संक्रमण रोग जैसे खुरपका, मुंहपका, गलाघोंटू, चिकिन पॉक्स, लंगड़ी, ज्वर इत्यादि के संक्रमण का खतरा बरसात में बढ़ जाता है। फलस्वरूप इलाज में पशुपालकों को धन हानि के साथ-साथ मानसिक परेशानी भी बढ़ जाती है। इन रोगों से बचाने के लिए टीकाकरण का कार्य प्रमुखता के साथ वर्षा शुरू होने से पहले कराया जाना अति आवश्यक है। अत: जिन पशुपालकों ने अपने पशुओं में टीकाकरण नहीं कराया है, वह सभी पशुपालक बीमारियों से बचाव के लिए टीकाकरण पशुपालन विभाग के सहयोग से अवश्य कराएं। बारिश के सीजन में बकरी पालक अपने बकरीयों को रोग से बचाने के लिए साफ-सुथरा और सूखे जगह का चयन करें।

मिर्च की खेती बनेगी लाभ का धंधा

कृषि विज्ञान केंद्र जावरा में हाल ही में कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन वर्चुअल किया गया। जिसमें कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख द्वारा बताया गया कि किसान किस तरह से मिर्च की फसल को आय का हिस्सा बनाएं, क्योंकि मिर्च को एक नगदी फसल के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसमें बहुत सारे विटामिन्स एवं खनिज लवण पाए जाते हैं। डॉ. ज्ञानेंद्र प्रताप तिवारी, वैज्ञानिक (पौध संरक्षण) द्वारा मिर्च फसल में लगने वाली कीट एवं व्याधियों के बारे में जानकारी दी गई कि किस तरह से मिर्च में लगने वाले कीड़े एवं बीमारियों के प्रकोप से रोका जाए। साथ ही फसल को बचाया जा सके। कीड़ों व बीमारियों में किस तरह से दवाओं का प्रयोग किया जाए। जिससे इनसे निजात पाई जा सके। प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान केवीके के डॉ. चतरा राम कांटवा, वैज्ञानिक (शस्य विज्ञान) ने खरपतवारनाशी के बारे में सुझाव दिए। केवीके के डॉ. बरखा शर्मा, डॉ. रामधन घसवा, डॉ. रोहताष सिंह भदौरिया, डॉ. डीआर पचौरी, डॉ. शिश राम जाखड़, मनोज कुमार रजक एवं योगेश कुमार साहू ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान लगभग 23 किसानों ने भाग लिया।

» सीधी जिले के सिहावल जनपद का मामला

» आरोपः समय पर नहीं पहुंचा चारा व भूसा

तीन माह में 61 गायों ने तोड़ा दम

संवाददाता, सीधी

जहां एक ओर राज्य सरकार गौशालाओं में तमाम सुविधाएं मुहैया कराने के लिए पानी की तरह पैसा खर्च कर रही है। वहीं दूसरी ओर मप्र के सीधी जिले की एक गौशाला में लापरवाही के चलते तीन माह के भीतर 61 गायों ने दम तोड़ दिया। लेकिन प्रशासन को भनक तक नहीं लगी और न ही गायों की मौत के कारण की जांच हो सकी।

दरअसल, यह शर्मनाक और चौंकाने वाला मामला सीधी के सिहावल जनपद क्षेत्र के सिहौलीया ग्राम पंचायत का है। यहां की गौशाला के देखरेख की जिम्मेवारी ग्राम पंचायत और एक महिला स्वयं सहायता समूह को सौंपी गई है। गौशाला में काम कर रहे महिला समूह को 10 महीने से पैसों का भुगतान नहीं किया गया है। अब जब महिला समूह ने मामले की शिकायत कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ से की तो अफसर भी दंग रह गए। आनन-फानन में मामले की जांच और दोषियों पर कार्रवाई का राग अलापने लगे।

भूख से हुई मौत!

सिहौलीया ग्राम पंचायत की गौशाला में तीन महीने के अंदर 61 गायों की मौत हो गई। यहां काम करने वाले समूह की महिलाओं का कहना है कि गायों के लिए समय पर चारा-भूसा नहीं पहुंचता, जिसके कारण भूख से गायों की मौत हुई है।

सौ गाय थीं रजिस्टर्ड

गायों की मौत के बाद यह गौशाला लगभग खाली हो गई है। पहले यहां सौ से ज्यादा गाय रजिस्टर्ड थीं। समूह की महिलाओं का कहना है कि पंचायत से सामग्रियों की मांग की जाती रही, लेकिन समय पर नहीं वितरण किया गया। न ही 10 महीने से समूह को भुगतान किया गया है।

गौशाला में पड़ा टैग

61 गायों की मौत के बाद गायों के कान में लगे रजिस्ट्रेशन नंबर की शील्ड गौशाला परिसर में पड़ी हैं। यहां हैरत की बात यह भी है कि इतनी गायों की मौत के बाद भी स्थानीय प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं लगी। इस मामले का राज भी महिलाओं ने खोला। इसके बाद हड़कंप मच गया है।

इनका कहना है

गौशाला में गायों की मौत और भुगतान न होने की शिकायत मिली है। मामले की जांच कराई जाएगी और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 8 जुलाई से पहले हमारे पास कोई शिकायत नहीं आई थी।

राकेश कुमार शुक्ला, सीईओ, जिपं सीधी

नसरुल्लागंज की गौशालाओं में चारा घोटाला!

» सीईओ के पास पहुंची शिकायत, जांच शुरू

» 18 गौशालाओं में से सिर्फ तीन में गौसेवा

संवाददाता, सीहोर

एक बार फिर चारा घोटाले का जिन्न बाहर निकला है, लेकिन इस बार मामला बीहार का नहीं, मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के नसरुल्लागंज ब्लॉक में संचालित 18 गौशालाओं में चारा घोटाले की शिकायत सामने आई है। इस शिकायत के बाद जिला पंचायत के अफसर सक्रिय होकर इन गौशालाओं में चारा घोटाले की जांच में जुट गए हैं।

दरअसल, मध्य प्रदेश गौ-संवर्धन बोर्ड की पहल पर प्रदेश के अन्य जिलों की तरह सीहोर के भी अलग-अलग ब्लॉक में गौशालाएं खोली गईं। ऐसे में जिले के नसरुल्लागंज ब्लॉक में संचालित 18 गौशालाओं में से फिलहाल तीन गौशालाओं में पशुओं की सेवा हो रही पा रही है, जबकि लगभग आधे से ज्यादा आज भी निर्माणाधीन हैं। ऐसे में ग्रामीणों द्वारा भेजी गई गड़बड़ी की शिकायत के बाद जनपद पंचायत शिकायतों की जांच करने में जुट गया है।

आवंटित राशि में गोलमाल

जांच इस बात की हो रही है कि कहीं बंद पड़ी इन गौशालाओं में चारे के नाम पर आवंटित राशि में कोई गोलमाल तो नहीं किया गया है। इन गौशाला में कई महीने से कोई गौवंश नहीं है। ऐसे में ग्रामीणों का आरोप है कि जब वह अपनी बूढ़ी गाय को वहां छोड़ने जाते हैं, तो उन्हें बहाने बनाकर भगा दिया जाता है।

कमचारियों को वेतन की लाले

निमोटा गांव के रहने वाले रामदीन के साथ-साथ इन गौशालाओं में काम पर रखे गए कर्मचारी भी आरोप लगाते दिखे कि उन्हें हर महीने मानदेय नहीं दिया जाता है। अगर दिया जाता है तो राशि टुकड़ों में दी जाती है। वहीं चौकीदार तकें सिंह ने बताया कि उन्हें दो माह से मानदेय नहीं मिला है।

इनका कहना है

ग्रामीणों की शिकायत पर मामले की जांच की जा रही है। अगर कोई भी दोषी मिला तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। हम यह भी जांच करा रहे हैं कि चारे के नाम पर आवंटित राशि में भी तो नहीं कहीं गोलमाल किया जा रहा है।

वृदावन सिंह मीना, सीईओ जनपद पंचायत, नसरुल्लागंज

इंदौर में ईसाई मिशनरी के अवैध कब्जे से मुक्त जमीन पर बन रही गौशाला

खुर्दा क्षेत्र उस महू विधानसभा सीट का हिस्सा है जिसकी विधायक उषा ठकुर हैं

संवाददाता, इंदौर

मध्य प्रदेश की संस्कृति और अध्यात्म मंत्री उषा ठाकुर ने कहा कि इंदौर जिले के खुर्दा क्षेत्र में ईसाई मिशनरी के कथित अवैध कब्जे से मुक्त कराई गई 70 बीघा जमीन पर आंगनबाड़ी और गौशाला बनाई जा रही है। खुर्दा क्षेत्र में ईसाई मिशनरी के अवैध कब्जे से 70 बीघा जमीन मुक्त कराई गई है जिस पर आंगनबाड़ी बनाई जा रही है। इस जमीन पर गौशाला भी बनाई जा रही है जिसे महिलाओं के एक स्वयंसहायता समूह को सौंपा जाएगा। गौरतलब है कि खुर्दा क्षेत्र उस महू विधानसभा सीट का हिस्सा है जिसकी उषा ठाकुर विधानसभा में नुमाइंदगी करती हैं।

अपशिष्ट फेंकने पर केस दर्ज

मंत्री ने यह भी बताया कि इंदौर जिले में अजनार नदी के पास हानिकारक रसायनों वाला औद्योगिक अपशिष्ट फेंके जाने के मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है और विस्तृत जांच के जरिये पता लगाया जा रहा है कि यह अपशिष्ट किन कारखानों से लाया गया था। अजनार नदी और इसके आस-पास के प्रदूषित क्षेत्र को एक निजी अपशिष्ट निवारण कंपनी की मदद से प्रदूषणमुक्त किया जा रहा है। लम्बे समय से औद्योगिक अपशिष्ट फेंके जाने के कारण न केवल अजनार नदी का पानी प्रदूषित हो गया है, बल्कि आस-पास के भूमिगत जल स्रोतों से भी प्रदूषित पानी निकल रहा है।

» रीवा व शहडोल संभाग में फसल को लेकर किसानों में घटी रुचि

» रीवा कृषि कॉलेज तैयार किया गया था जेके-49 किस्म का कोदौ

तमिलनाडू, आंध्र और कर्नाटक में लहलहा रही विंध्य की कोदौ

संवाददाता, रीवा। रीवा और शहडोल संभाग की प्रमुख फसलों में से एक कोदौ समय के साथ अब यहां के खेतों से गायब होती जा रही है। इस फसल में किसानों की रुचि घटी है और वे फसल की बोवनी करना धीरे-धीरे करके बंद कर दिए हैं। जबकि विंध्य क्षेत्र में तैयार होने वाले कोदौ को साउथ के किसानों ने काफी पसंद किया है और इसकी अच्छी खेती तमिलनाडू, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक जैसे राज्यों में किसान कर रहे हैं। विंध्य की यह फसल अब साउथ की जमीनों में लहलहा रही है। अपनी औषधि एवं गुणों से भरपूर कोदौ के महत्व को देखते हुए रीवा कृषि कॉलेज अनुसंधान केंद्र में इस पर नई तकनीक का उपयोग करते हुए जेके-49 कोदौ तैयार किया था और इसे देश के सभी अनुसंधान केंद्रों में भेजा गया है। जहां साउथ के अनुसंधान केंद्र में इस फसल को रिसर्च के बाद तैयार किया गया और किसानों को इस फसल का बीज भी उपलब्ध कराया गया, जहां किसान जेके-49 कोदौ की खेती करने में रुचि ले रहे हैं। यही वजह है कि साउथ में कोदौ की अच्छी पैदावार हो रही है।

औषधि तत्वों से भरा कोदौ

कृषि कालेज के अधिकारियों ने बताया कि जो कोदौ विंध्य क्षेत्र में तैयार होता था उसे और बेहतर बनाया गया। यह कोदौ औषधि तत्वों से भरपूर है। कोदौ का अनाज शरीर के लिए लाभकारी है तो वहीं डायबटीज मरीजों के लिए यह अनाज सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है। इसे सुगर फ्री चावल के नाम से भी अब पहचान मिल रही है। इस फसल को तैयार करने में किसानों को ज्यादा परिश्रम भी नहीं करना पड़ता है। कारण यह कि कम पानी में यह फसल तैयार हो जाती है और इसमें बीमारी भी ज्यादा नहीं लगती है।

कृषि कॉलेज ने तैयार किया नया बीज

बताया जा रहा है कि विंध्य में पूर्व में जो कोदो तैयार होता था उसके पौधे लचीले होते थे और हवा पानी में गिर जाते थे। कृषि कॉलेज के वैज्ञानिकों ने अनुसंधान केंद्र में इसे और मजबूती देकर नया बीज तैयार किया और इसे जेके-49 नाम देकर सभी देश के सभी अनुसंधान केंद्रों में भेजा गया था। अब यह फसल खेत में मजबूती के साथ तैयार होती है और पानी हवा का इतना असर इसमें नहीं पड़ता है। स्थानीय किसानों में

इस फसल को लेकर रुचि कम होने के पीछे बाजार में कोदौ के अनाज की मांग को कम होना और पर्याप्त पानी मिलने के कारण किसानों में धान की रोपाई करने में ज्याद रुचि है, जिसके चलते यह फसल विंध्य की धरती से धीरे-धीरे गायब होती जा रही है।

अच्छी पैदावार

कृषि वैज्ञानिकों ने कोदौ की जो नई किस्म तैयार की है वह फार्म हाऊस के नियमानुसार अगर खेतों में तैयार की जाए तो 28 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन होगा। जबकि सामान्य रूप से खेती करने पर 15 से 18 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जेके-49 कोदौ किसान तैयार कर सकते हैं।

बाजार में 80 रुपए किलो

कृषि कालेज के वैज्ञानिकों द्वारा तैयार किए गए कोदौ को स्थानीय किसानों के बीच भी तैयार करने के लिए प्रयास किए गए, लेकिन किसानों में रुचि न होने के कारण इस फसल की बोवनी अभी किसान नहीं कर रहे हैं। जबकि मंडी में कोदौ की कीमत भी अब बढ़ने लगी है और 70 से 80 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक्री हो रही है। डायबटीज के मरीज चावल छोड़कर कोदौ का अनाज खाने में उपयोग करने लगे हैं। यही वजह है कि बाजार भाव इसका बढ़ रहा है।

इनका कहना है

साउथ के किसान अपने खेतों में अब कोदौ की खेती अच्छी कर रहे हैं। इसका बीज रीवा में तैयार किया गया था और सभी अनुसंधान केंद्रों को भेजा गया, जहां साउथ के अनुसंधान केंद्र ने इस बीज को तैयार किया और किसान इसकी बोवनी कर रहे हैं।

डॉ. एसके पांडेय, अधिष्ठाता, कृषि कॉलेज, रीवा

गाय का गोबर सरकार खरीदेगी पांच रुपए किलो

» दिल्ली, वाराणसी व नासिक में खादी ग्रामोद्योग देगा दाम

» छह राज्यों में जल्द लगेगी प्राकृतिक पेंट बनाने की यूनिट

संवाददाता, भोपाल/नई दिल्ली

गाय से मिलने वाला घी-दूध ही नहीं, बल्कि गोबर भी आमदनी का जरिया बन गया है। पारंपरिक रूप से खाद के रूप में इस्तेमाल किए जा रहे गोबर को बेचकर भी पैसा कमाया जा सकता है। गाय के गोबर को कोई और नहीं, बल्कि खुद सरकार खरीदेगी। साथ ही लोगों को आमतौर पर मिलने वाली गोबर की कीमत के मुकाबले चार गुना मोटा पैसा भी देगी। हालांकि अभी इसके लिए मप्र में गौपालकों और गौशाला संचालकों को इंतजार करना पड़ेगा। यह व्यवस्था अभी मप्र में लागू नहीं हो रही है। अभी खादी ग्रामोद्योग आयोग छह राज्यों में जल्द ही गाय के गोबर से प्राकृतिक पेंट बनाने की यूनिट डालने जा रहा है। गौरतलब है कि जनवरी में ही राजस्थान के जयपुर में पहली बार खादी ग्रामोद्योग आयोग की ओर से गाय के गोबर से प्राकृतिक पेंट बनाकर लांच किया गया था। हालांकि अब देश के छह बड़े शहरों में भी गाय के गोबर से प्राकृतिक पेंट बनाने के लिए मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट लगाने की तैयारी की जा रही है। इनमें देश की राजधानी दिल्ली सहित अहमदाबाद, बंगलुरू, यूपी के वाराणसी, नासिक और ओडीसा के चौद्वार शहर शामिल हैं।

छह राज्यों को चुनाव

खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के अनुसार केवीआईसी की ओर से छह राज्यों को चुना गया है। यहां के बड़े और प्रमुख शहर में एक-एक यूनिट लगाकर गाय के गोबर से प्राकृतिक पेंट बनाया जाएगा। वहीं जो सबसे खास बात होगी वह यह होगी कि इन्हीं शहरों के आसपास के लोगों से इसके लिए गाय का गोबर खरीदा जाएगा।

मिलेगा चार हजार महीना

केवीआईसी के अधिकारियों का कहना है कि पांच रुपए प्रति किलोग्राम गोबर बेचकर लोगों को काफी मुनाफा हो सकता है। आमतौर पर एक स्वस्थ गाय दिन में 20 से 25 किलोग्राम तक गोबर करती है। ऐसे में पांच रुपए प्रतिकिलो के हिसाब से देखें तो एक गाय के गोबर को बेचने से ही रोजाना 100 से 125 रुपए तक की कमाई की जा सकती है। साथ ही महीने का तीन हजार से चार हजार रुपए तक एक गाय से कमाया जा सकता है। जबकि गाय का दूध और घी आदि अलग चीजें हैं।

ईको फ्रेंडली पेंट की बढ़ी मांग

छह महीने पहले लांच हुए प्राकृतिक पेंट की मांग लगातार बढ़ रही है। लोग अपने घरों को इससे रंग रहे हैं। कुछ दिन पहले ही खादी ग्रामोद्योग आयोग के वरिष्ठ अधिकारी की ओर से बताया गया था कि इसकी सेल काफी बेहतर है।

इनका कहना है

आम लोगों, गौशालाओं से पांच रुपए किलो गाय का गोबर खरीदा जाएगा। अभी तक लोग एक से डेढ़ रुपए प्रति किलो की दर पर खाद या परंपरागत चीजों के लिए गाय के गोबर को बेचते रहे हैं। या फिर इसके उपले बनाकर बेचते हैं। जिसमें लागत और श्रम भी लगता है लेकिन अब केवीआईसी इसके करीब चार से पांच गुना ज्यादा दाम देकर गोबर को खरीदेगा।

विनय कुमार सक्सेना, चेयरमैन, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग

सागर के प्याज उत्पादक किसान होंगे आत्मनिर्भर

सागर। सागर के प्याज उत्पादक किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जिले में उपयुक्त बाजार उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए शीघ्र ही विस्तृत कार्ययोजना बनाई जाए। सागर की प्याज की पहचान के लिए ब्रांडिंग भी की जाएगी। यह बात हाल ही में सागर कलेक्टर दीपक सिंह ने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी वर्चुअल कान्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न अधिकारियों से कही। इस अवसर पर उद्यानिकी विभाग के उपसंचालक एसके रेजा, कृषि विभाग के उपसंचालक बीएल मालवीय, कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक एके त्रिपाठी, लीड बैंक मैनेजर दीपेंद्र यादव सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। कलेक्टर ने बताया कि केंद्र सरकार की आत्मनिर्भर अमृत महोत्सव योजना के तहत मध्य प्रदेश में तीन जिलों का चयन किया गया है जिसमें सागर, दमोह और इंदौर शामिल हैं। सागर में 9927 हेक्टेयर रकवा में प्याज का उत्पादन किया जा रहा है।

- कलेक्टर बोले:
- उपलब्ध कराएंगे उपयुक्त बाजार
- केंद्र की अमृत महोत्सव योजना में तीन जिले शामिल
- जिले में 9000 हेक्टेयर क्षेत्र में हो रही प्याज की खेती

प्याज के उत्पादन पर फोकस: समस्त प्याज उत्पादकों की उद्यानिकी विभाग के माध्यम से पंजीयन किए जाएं वह सूची तैयार की जाए। उन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों के माध्यम से तकनीकी मार्गदर्शन लेने के लिए प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जाए। जिसमें जिले के प्याज उत्पादकों को आमंत्रित किया जाए। प्याज का उत्पादन बढ़ाने के लिए महिला स्व सहायता समूह की सहभागिता भी सुनिश्चित की जाएगी। प्याज की विभिन्न प्रकार की किस्मों की जानकारी लेकर प्रशिक्षण में प्रस्तुत की जाए।

- मध्य प्रदेश विधानसभा में तैयार की जा रही असंसदीय शब्दों की सूची
- सदस्यों को नौ अगस्त से होने वाले मानसून सत्र से पहले होगी वितरित
- कोरोना का टीका लगवाने के बाद ही सदस्यों को मिलेगा सदन में प्रवेश

माननीय अब नहीं बोल पाएंगे 'पप्पू-फेंकू और बंटाधार'

विशेष संवाददाता, भोपाल

विधानसभा में अब सदस्य पप्पू, फेंकू, बंटाधार, चोर, झूठा, मूर्ख सहित अन्य शब्दों का उपयोग नहीं कर पाएंगे। इसके लिए विधानसभा सचिवालय असंसदीय शब्दों की सूची तैयार कर रहा है। नौ अगस्त से होने वाले विधानसभा के मानसून सत्र के पहले सदस्यों को शब्दों की यह सूची उपलब्ध कराई जाएगी। इसके साथ ही सदन में सदस्यों को प्रवेश कोरोना टीका लगवाने के बाद ही मिलेगा। उन्हें सचिवालय को इससे संबंधित प्रमाण पत्र बनाना होगा। अधिकारियों का कहना है कि 85 फीसद विधायकों को टीका लग चुका है।

विधानसभा के प्रमुख सचिव अवधेश प्रताप सिंह ने बताया कि लोकसभा सचिवालय सहित अन्य विधानसभाओं से ऐसी शब्दों की सूची बुलाई है, जिनका उपयोग नहीं करने की अपेक्षा सदस्यों से की गई है। इसके साथ-साथ सदन की कार्यवाही के दौरान जिन शब्दों को विलोपित किया गया है, उन्हें शामिल करते हुए मार्गदर्शिका तैयार की जा रही है। कोशिश यह है कि विधानसभा सत्र के पहले यह सदस्यों को वितरित कर दी जाए। बताया जा रहा है कि इसमें नालायक, बेवकूफ सहित अन्य शब्दों को शामिल किया है।

सदन की मर्यादा को बनाए रखने के जिम्मेदारी सभी सदस्यों की होती है। हमारा आचरण सदन में ऐसा होना चाहिए, जो दूसरों के लिए मिसाल हो। कई बार आवेग में सदन में ऐसे शब्दों का उपयोग हो जाता है, जिन्हें कार्यवाही से विलोपित करना पड़ता है। ऐसे शब्दों का उपयोग सदस्य न करें, इसके लिए मार्गदर्शिका तैयार कराई गई है। इसे सदस्यों को सत्र के पूर्व दिया जाएगा। साथ ही उन्हें प्रशिक्षण भी दिया जाएगा कि किस तरह उन्हें प्रश्न पूछने चाहिए ताकि उत्तर सदन में ही मिल जाए। प्रशिक्षण को लेकर सभी से सहमति मांगी गई है ताकि इसमें गंभीरता रहें।

गिरीश गौतम, अध्यक्ष, मप्र विधानसभा

नईगढ़ी पहुंचेगा सोन का पानी

इधर, विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने कहा कि देवतालाब विधानसभा क्षेत्र में रहने वाले प्रत्येक परिवार को पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। देवातालाब विधानसभा क्षेत्र के विकास की तस्वीर बदलदूंगा। इसके लिए मैं पूर्णरूपेण समर्पित होकर काम कर रहा हूं। देवतालाब में प्रत्येक ग्राम को सड़क मार्ग से जोड़ने के लिए सड़कों का जाल बिछाया गया है। नईगढ़ी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बाउंड्रीबॉल, कम्युनिटी हाल, पोस्टमार्टम रूम एवं मरीजों के साथ आने वाले परिजनों के रुकने के लिए आश्रय स्थल के निर्माण के लिए एक करोड़ की स्वीकृति दी गई है। नईगढ़ी के किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए बहुती नहर के माध्यम से सोन नदी का पानी लाने के लिए 7 करोड़ 50 लाख रूपये की स्वीकृति प्राप्त हुई है। उन्होंने कहा कि मैं देवतालाब विस में विकास के लिए समर्पित एवं कृत संकल्पित होकर काम कर रहा हूं।

भोपाल में दस और ग्वालियर में 21 साल में पहली बार हुई कम बारिश

मप्र में सूखे का रिकॉर्ड

- सोयाबीन की 42 लाख, धान की 11 लाख हेक्टेयर में बोवनी
- किसान चिंतितः जो फसल लगा दी है वो भी अब मुरझा रही

वर्षाकाल का लगभग एक माह बीत चुका है, लेकिन मध्यप्रदेश में मानसून अब तक सक्रिय नहीं हो पाया है। प्रदेश के 52 जिलों में से आधे जिलों में अब भी सामान्य से कम बारिश हुई है। वहीं भोपाल, ग्वालियर में सूखे के हालात निर्मित हो गए हैं। भोपाल में जुलाई माह में कम बारिश से 10 साल का रिकॉर्ड टूट गया तो वहीं ग्वालियर में भी जुलाई माह में कम बारिश का 21 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। अगले दो माह में मानसून प्रदेश में रिकवर नहीं करता है तो अगले वर्ष भयंकर सूखे का सामना करना पड़ सकता है। यही नहीं, अधिकांश जगह किसानों की फसल भी पानी नहीं मिलने के कारण चौपट हो गई है। अब दोबारा बोवनी करनी पड़ेगी।

संवाददाता, भोपाल

प्रदेश में मानसून के रूठने का असर खरीफ फसलों की बोवनी पर पड़ रहा है। सोयाबीन की बोवनी का लक्ष्य 61 लाख हेक्टेयर रखा था, लेकिन अभी तक 42 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में ही बोवनी हो पाई है। धान भी 34 लाख की जगह 11 लाख हेक्टेयर में ही लग पाई है। बारिश नहीं होने से किसान चिंता में हैं, क्योंकि जो फसल लगा दी है वो भी मुरझा रही है। यदि ऐसे ही हालात दस दिन और रहे तो सोयाबीन की फसल लेने में जोखिम बढ़ जाएगा। हालांकि, कृषि विभाग उम्मीद जता रहा है कि एक सप्ताह के भीतर मानसून सक्रिय हो जाएगा और बोवनी की गति भी बढ़ जाएगी।

प्रदेश में इस बार 149 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ फसलों की बोवनी का लक्ष्य तय किया गया है, पर मानसून के सक्रिय न होने से बोवनी प्रभावित हो रही है। कृषि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि मानसून की स्थिति को देखते हुए जिन किसानों के पास सिंचाई के स्वयं के साधन हैं वे ही बोवनी कर रहे हैं। सलाह भी यही दी गई है कि जल्दबाजी न करें, क्योंकि बारिश जल्द न हुई तो बीज खराब हो सकता है। दरअसल, खरीफ फसलों के लिए तापमान सामान्य से अधिक है। जहां बोवनी हो भी गई है, वहां भी बारिश न होने से यह प्रभावित हो रही है।

मक्का का बढ़ेगा रकबा

सोयाबीन की फसल के लिए 61 लाख हेक्टेयर का लक्ष्य रखा है, लेकिन अभी तक बोवनी 42 लाख हेक्टेयर में ही हुई है। इसी तरह धान भी 34 लाख हेक्टेयर की जगह करीब 11 लाख हेक्टेयर में ही लग पाई है। मक्का की बोवनी जरूर 13.82 लाख हेक्टेयर में हो गई है। इसके लिए लक्ष्य 14.91 लाख हेक्टेयर रखा है, जिसे बढ़ाया जा सकता है। वहीं, अरहर तीन लाख हेक्टेयर, उड़द साढ़े आठ लाख, मूंग 93 हजार और ज्वार 81 हजार हेक्टेयर में बोई गई है।

करना चाहिए इंतजार

यदि बारिश की स्थिति यही रहती है फिर 15 जुलाई के बाद किसानों को सोयाबीन की बोवनी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फिर फसल के अनुकूल स्थिति नहीं रह जाती है। कीट व्याधि से फसल प्रभावित होने लगती है। धान की बोवनी अगस्त तक होती है, इसलिए किसानों के पास अभी समय है। उन्हें इंतजार करना चाहिए और कम पानी में भी तैयार होने वाली ज्वार, मक्का, मूंग, उड़द, बाजरा, तिल आदि फसल लेनी चाहिए।

अब तक खरीफ फसलों को 20 से 25 प्रतिशत नुकसान हो चुका है। पिछले 15 दिन से पानी नहीं गिरा है। जिन्होंने धान लगा दी, उनके बीज खराब हो रहे हैं। वैसे भी जब चार इंच जमीन गिली न हो जाए तब तक धान की बोवनी नहीं करनी चाहिए। स्थिति यह बन रही है कि फसल दोपहर में मुरझा जाती है और शाम को नमी होने पर ठीक दिखने लगती है।

■ डॉ.जीएस कौशल, पूर्व कृषि संचालक

प्रोत्साहित करने संबंधी मामले में कानून का मसौदा सीएम के सामने आया

निजी भूमि पर पौधारोपण कानून बनाने से पहले जनता से राय लेगी सरकार

संवाददाता, भोपाल

निजी भूमि पर पौधारोपण को प्रोत्साहन करने के लिए राज्य सरकार कानून बना रही है। इसका प्रारूप तैयार हो चुका है जिस पर अब जनता से राय ली जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने कानून का मसौदा रखा गया। उन्होंने पर्यावरणविदों, वन विशेषज्ञों, जनजातीय जीवन के अध्येताओं, राजस्व विभाग के विशेषज्ञों सहित जनसामान्य और किसानों से सुझाव लेने के निर्देश दिए हैं। कानून के मसौदे पर चर्चा के लिए मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित इस बैठक में मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस, कृषि उत्पादन आयुक्त केके सिंह, प्रमुख सचिव किसान कल्याण अजीत केसरी, प्रमुख सचिव वन अशोक वर्णवाल तथा अन्य अधिकारी मौजूद थे। सरकार ने वृक्षारोपण प्रोत्साहन विधेयक-2021 का प्रारूप तैयार कर लिया है। जिसमें किसानों, आमजन को निजी भूमि पर पौधे लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना है। इस कानून में सरकार आमजन को सभी प्रजातियों के पौधे लगाने और उन्हें जरूरत पड़ने पर काटने की अनुमति देगी।

नहीं लेनी होगी अनुमति

आमजन अपनी भूमि पर खड़े पेड़ बगैर किसी अनुमति के काट सकेंगे और टाल लगाकर लकड़ी बेच भी सकेंगे। लकड़ी के परिवहन पर ट्रांजिट परमिट (टीपी) की छूट भी दी जाएगी। वर्तमान में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व (एसडीएम) से अनुमति लेकर ही निजी भूमि पर खड़े पेड़ काटे जा सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता की राय लेने से कानून को अधिक व्यावहारिक और प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी और कानून के प्रविधानों के संबंध में जनसामान्य में जागरूकता भी बढ़ेगी।

आवश्यकता

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर और मुरैना से प्रकाशित

जागत गांव हमार

कृषि और पंचायत पर आधारित साप्ताहिक समाचार पत्र के लिए जिला, जनपद स्तर पर संवाददाता चाहिए।

संपर्क करें

जबलपुर, प्रवीण नामदेव-9300034195
शहडोल, गोपाल दास बंसल-9131886277
नरसिंहपुर, प्रहलाद कौरव-9926569304
हरदा, राजेन्द्र बिल्लोरे-9425643410
विदिशा, अवधेश दुबे- 9425148554
सागर, अनिल दुबे-9826021098
राहतगढ़, भगवान सिंह प्रजापति-9826948827
दमोह, बंटी शर्मा -9131821040
टीकमगढ़, नीरज जैन -9893583522
राजगढ़, गजराज सिंह मीणा -9981462162
मुरैना, अवधेश दण्डोतिया -9425128418
शिवपुरी, खेमराज मौर्य-9425762414
भिण्ड- नीरज शर्मा-9826266571
खरगौन, संजय शर्मा-7694897272
सतना, दीपक गौतम-9923800013
रीवा-धनंजय तिवारी-9425080670
रतलाम, अमित निगम-70007141120
झाबुआ-नोमान खान-8770736925

कार्यालय का पताः- लाजपत भवन प्रथम तल, आईसीआईसीआई बैंक के पास, एमपी नगर, जोन-1, भोपाल, मप्र,
संपर्क करें- 07554064144, 9229497393, 9425048589

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक अजय कुमार द्विवेदी द्वारा जय माता प्रिंटर्स, मं.नं.1, पेमदीपुरा बापू कालोनी के पास चिकलोद रोड, जहांगीराबाद, भोपाल(मप्र) से मुद्रित एवं एमआईजी 30, शिवकल्प, अयोध्या बाईपास भोपाल, मप्र से प्रकाशित। संपादक: अजय कुमार द्विवेदी, स्थानीय संपादक- **सतीश उपाध्याय, संपर्क** -9229497393, 9425048589, ईमेल:- jagatgaon.bpl@gmail.com (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल होगा)